

प्रक्रिया सुधार: अनिश्चितता के तहत निर्णय लेने को सक्षम करना

असमानता के सभी रूपों में, स्वास्थ्य सेवा में अन्याय सबसे चौंकाने वाला
और सबसे अमानवीय है।

—Martin Luther King Jr.

अंतर्राष्ट्रीय तुलना से पता चलता है कि भारत की प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समस्याएं प्रक्रिया या विनियामक मानकों के अनुपालन की कमी से कम होती हैं, लेकिन अति-विनियमन से। इस अध्याय में, एक कंपनी द्वारा भारत में स्वैच्छिक परिसमापन से गुजरने के लिए किए गए समय और प्रक्रियाओं के एक मामले के अध्ययन के माध्यम से अति-विनियमन के मुद्दे को चित्रित किया गया है। यहां तक कि जब कोई विवाद/मुकदमेबाजी नहीं होती है और सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है, तो रिकॉर्ड से अलग होने में 1570 दिन लगते हैं। यह अन्य देशों की तुलना में अधिक परिमाण की कोटि है।

अधूरे अनुबंधों की रूपरेखा का उपयोग करते हुए, अध्याय का तर्क है कि भारतीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अतिरंजना और अस्पष्टता की समस्या पूर्ण नियमों की आवश्यकता पर जोर देती है जो हर संभव परिणाम के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक ओर 'विनियमन' और 'पर्यवेक्षण' के बीच अंतर की अपर्याप्त वृद्धि के कारण है, और दूसरी ओर अपूर्ण नियमों की अनिवार्यता है। वास्तविक-विश्व नियमन जिन संयोजन के कारण अनिवार्य रूप से अधूरा है: (i) “अज्ञात को ज्ञात नहीं” के कारण बद्ध तर्कसंगतता, (ii) “पूर्ण” अनुबंधों को प्रत्याशित और निधिरित करने में शामिल जटिलता, जो सभी संभावित आकस्मिकताओं के दौरान सभी दायित्वों को पूर्ण रूप से निर्दिष्ट करना और (iii) तीसरे पक्ष के लिए निर्णयों को सत्यापित करने में आने वाली कठिनाई है। यह निर्णय करने में विवेक को अनिवार्य बनाता है। यह सबूत दर्शाते हैं कि अति-विनियमन, ना कि सामान्य विनियमन, अवरूद्ध निर्णय क्षमता की ओर ले जाता है।

समस्या यह है कि नीति निर्माताओं की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो पर्यवेक्षण के विपरीत आदेशक विनियमन का अधिक पक्ष लेती है। पर्यवेक्षण के विपरीत विनियमन को आसानी से मापा जा सकता है। आखिरकार, नियम मानदंड या चेकलिस्ट प्रदान करते हैं, जिससे नियामकों के लिए बाद में अनुपालन सरल और जवाबदेही कम हो जाती है। इसके विपरीत, पर्यवेक्षण की मात्रा और गुणवत्ता को निर्धारित करना मुश्किल है।

इष्टतम समाधान के लिए पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ संयुक्त सरल नियम हैं। सरकार के निर्णय निर्माता को विवेक के साथ प्रदान करने के बाद, यह तीन चीजों के साथ

संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है- बेहतर पारदर्शिता, पूर्व- घटना की मजबूत प्रणाली (जैसे बैंक बोर्ड) और पूर्व-पोस्ट रिजॉल्यूशन तंत्र। एक उदाहरण के रूप में, अध्याय बताता है कि नए सरकारी ई मार्केटप्लेस (GeM portal) ने सरकारी खरीद में मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता को कैसे बढ़ाया है। इससे न केवल खरीद की लागत में कमी आई है, बल्कि ईमानदार सरकारी अधिकारी के लिए निर्णय लेना भी आसान हो गया है।

नियामक प्रभावशीलता की समस्या

6.1 यह अक्सर माना जाता है कि भारत की नियामक समस्याएं, नियामक मानकों की कमी और प्रक्रिया के खराब अनुपालन के कारण हैं। अंतरराष्ट्रीय तुलना, हालांकि, यह बताती है कि सही नियामक मानकों को रखने और प्रक्रिया के अनुपालन के मामले में भारत अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर रैंक पर है। वास्तविक मुद्दा नियमों की प्रभावशीलता का है, जो अनुचित देरी, मालगुजारी की मांग, जटिल नियम और विनियमन की गुणवत्ता के कारण होता है।

6.2 विश्व न्याय परियोजना¹ द्वारा प्रकाशित 'वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स' नियामक प्रवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर क्रॉस कंट्री की तुलना प्रदान करता है। सूचकांक में विभिन्न उप-श्रेणियां हैं, जो नियत प्रक्रियाओं, प्रभावशीलता, समयसीमा आदि के अनुपालन को सुनिश्चित करती हैं। 2020 में, 'उपयुक्त प्रक्रिया का प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सम्मान किया जाता है' की श्रेणी में भारत की रैंक 128 देशों में 45 है। इसके विपरीत, 'सरकारी नियम प्रभावी रूप से लागू किए जाते हैं' (नियामक गुणवत्ता/प्रभावशीलता के लिए प्रॉक्सी) श्रेणी में देश की रैंक 104 (तालिका 1) है। प्रशासनिक कार्यवाही अनुचित विलंब के बिना आयोजित की जाती है (समयबद्धता के लिए प्रॉक्सी) में भारत 89 वीं रैंक पर है और प्रशासनिक कार्यवाही लागू होती है और अनुचित प्रभाव के बिना लागू होते हैं (किराए की मांग के लिए प्रॉक्सी) में 107वां स्थान है। इससे पता चलता है कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत, भारत प्रक्रियाओं के अनुपालन में अपेक्षाकृत अच्छा है, लेकिन नियामक प्रभावशीलता में पिछड़ जाता है।

6.3 वास्तव में, प्रशासनिक कार्यवाही में उचित प्रक्रिया के अनुपालन में भारत के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, 2015 में 72वीं रैंक (102 देशों में से) से 2020 में 45वीं रैंक (128 देशों में से) का सुधार हुआ है। इसके विपरीत, यह अन्य मापदंडों पर समय के साथ कमी हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नियम और प्रक्रिया को लागू करना एक बात है, जबकि उनकी प्रभावशीलता दूसरी बात है।

तालिका 1: विनियामक प्रवर्तन की विभिन्न श्रेणियों में भारत की रैंक

	2015	2020
विनियामक प्रवर्तन समग्र रैंक	69	74
सरकारी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है	87	104
सरकारी नियम लागू किये गए हैं और अनुचित प्रभाव के बिना लागू किये गए हैं।	74	107
बिना किसी देरी के प्रशासनिक कार्यवाही की गई है	75	89
प्रशासनिक कार्यवाही में विधिवत प्रक्रिया का सम्मान किया गया है	72	45
देशों की संख्या	102	128

स्रोत: विश्व न्याय परियोजना

6.4 सूचकांक से यह भी पता चलता है कि यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और कनाडा को नियत प्रक्रिया और नियामक प्रभावशीलता के बाद दोनों के मामले में भारत की तुलना में बहुत बेहतर रखा गया है। हालांकि, नियत प्रक्रियाओं की तुलना में भारत और इन देशों के बीच का अंतर नियामक प्रभावशीलता में बहुत

व्यापक है। इसी तरह, भारत को अन्य ब्रिक्स देशों (दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर) को नियत प्रक्रिया के सम्मान के मामले में बेहतर माना जाता है, लेकिन, उन मानकों (तालिका 2) की प्रभावशीलता में उनसे भी बदतर है।

तालिका 2: 2020 में नियामक मानकों और नियामक प्रवर्तन की तुलना

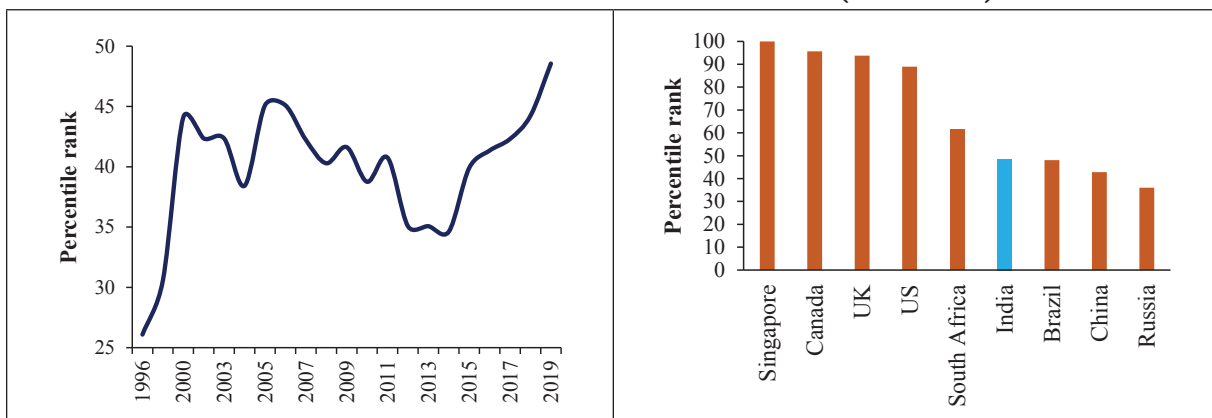
रैंक	अमेरिका	ब्रिटेन	सिंगापुर	कनाडा	ब्राजील	रूस	चीन	दक्षिण अफ्रीका	भारत
विनियामक प्रवर्तन	20	13	3	11	60	73	67	45	74
सरकारी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है	20	11	5	12	62	47	63	92	104
सरकारी नियम लागू किये गए हैं और अनुचित प्रभाव के बिना लागू किया गया है।	16	9	4	8	64	83	63	59	107
बिना किसी देरी के प्रशासनिक कार्यवाही की गई है	33	13	1	17	124	24	23	48	89
प्रशासनिक कार्यवाही में विधिवत प्रक्रिया का सम्मान किया गया है	18	12	7	5	55	97	98	25	45

स्रोत: विश्व न्याय परियोजना (2020)

6.5 इसी निष्कर्ष को विभिन्न विश्व बैंक अध्ययनों से प्राप्त किया जा सकता है। इसके नियामक गुणवत्ता सूचकांक² से पता चलता है कि 2013 (चित्र 1) के बाद से भारत की नियामक गुणवत्ता में सुधार के बावजूद, यह अभी भी यूके, यूएस, सिंगापुर, जापान आदि (चित्र 2) की तुलना में बहुत कम है। इसी तरह, (विश्व बैंक की व्यवसाय करने में आसानी) वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) रिपोर्ट बताती है कि समग्र ईओडीबी रैंक में भारी प्रगति करने के बावजूद, भारत अभी भी उप-श्रेणियों में 'व्यापार शुरू करने' और 'संपत्ति दर्ज करने' में पीछे है, जहां देश की रैंक क्रमशः 136 और 154 है। रिपोर्ट बताती है कि एक कंपनी का कानूनी रूप से शुरू करने और औपचारिक रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की उच्च संख्या इसका कारण है और साथ ही साथ प्रत्येक प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय और लागत है।

चित्र 1: भारत में नियामक गुणवत्ता

चित्र 2: नियामक गुणवत्ता की क्रॉस कंट्री तुलना (2019 तक)



स्रोत: विश्व बैंक (2019)

नोट: चित्र 1 और 2 में, उच्च संख्या सुधार की सूचक है (अन्य रैंकिंग के विपरीत)

¹ विश्व न्याय परियोजना को अमेरिकन बार एसोसिएशन की पहल के रूप में 2006 में स्थापित किया गया और 2009 में यह एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन बना। विश्व न्याय परियोजना द्वारा प्रकाशित आंकड़े विश्व बैंक द्वारा अपने विश्व शासन सूचकांक में उपयोग किए जाते हैं।

6.6 भारत में अनावश्यक विनियमन के दृष्टांत के रूप में, किसी कंपनी के स्वैच्छिक बंद होने के मामले को लेते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (आर्थिक सर्वेक्षण के लिए किया गया) द्वारा किया गया एक केस अध्ययन दर्शाता है कि वास्तव में कंपनी के रजिस्ट्रार से हटने वाली कंपनी के निर्णय के ठीक समय से लिया गया समय 1570 दिन (यानी 4.3 वर्ष) है, भले ही सभी कागजी कार्रवाई सही हो और कंपनी किसी मुकदमेबाजी या विवाद में शामिल नहीं है। यह एक नियमित गतिविधि का सबसे अच्छा संभावित मामला है। दिलचस्प बात यह है कि कुल समय में से लगभग 1000 दिन, आयकर, भविष्य निधि, जीएसटी विभाग द्वारा मंजूरी के लिए लिए जाते हैं और विभिन्न विभागों से सुरक्षा रिफंड वापस लेने में लगते हैं (तालिका 3)। इसके विपरीत, स्वैच्छिक परिसमापन, सिंगापुर में लगभग 12 महीने, जर्मनी में 12-24 महीने और ब्रिटेन में 15 महीने लगते हैं। जर्मनी में, बहुत बड़ी और सक्रिय कंपनियों के लिए, 2-4 साल लगते हैं। विवादों और मुकदमों की संभावना को देखते हुए, तुलनीय बड़े मामलों के लिए भारत में एक दशक तक का समय लग सकता है।

तालिका 3: भारत में स्वैच्छिक परिसमापन में कंपनी द्वारा सामना किये जाने वाली समयरेखा और प्रक्रियाएँ (जब मुकदमेबाजी/विवाद न हो तो भी)

समयरेखा (दिन)	प्रक्रियाएँ
T	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी का भारत में अपने व्यवसाय संचालन को बंद करने का निर्णय
T +16	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी द्वारा भारत में अपने व्यवसाय संचालन को बंद करने के लिए बोर्ड के प्रस्ताव को पारित करना
T + 20 to T + 70	<ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक घोषणा, कर्मचारियों को सूचना और परिसमापक को कानूनी इकाई में परिवर्तन की रणनीति
T + 70 to T + 110	<ul style="list-style-type: none"> कर्मचारियों का बहुमत से बाहर निकलना; विक्रेताओं को सूचना भौतिक डेटा और रिकॉर्ड की पहचान और प्रमुख भौतिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण बहीवाता गतिविधि के लिए पेशेवर फर्म का परिचय आगे बढ़ रहा है अंडरटेकिंग बिक्री/वसूली और चल संपत्ति का निपटान
T + 110 to T + 200	<ul style="list-style-type: none"> व्यवसाय संचालन और अनुबंधों को समाप्त करने की छूट आयकर अधिकारियों को सूचित करना शेष प्रमुख कर्मचारियों का बाहर निकलना; परिसंपत्ति निपटान प्रक्रिया को पूरा करना औद्योगिक कार्यों की निगरानी करने वाले सरकारी निकायों के साथ चिह्नित लंबित वैधानिक अनुपालन और समापन प्रक्रिया को पूरा करना। सभी विक्रेताओं से कोई बकाया प्रमाण पत्र नहीं मांग रहा है NCLT द्वारा विघटन का आदेश पारित होने तक स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया की अवधि के दौरान निवासी भारतीय निदेशक की पहचान और नियुक्ति*
T + 200 to T + 270	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय निवासी निदेशक सहित नए बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति ' वित्तीय गड़बड़ी के जोखिम को कम करने के लिए मौजूदा बैंक खातों में बैंकिंग परिचालन को समाप्त करना स्वैच्छिक परिसमापन शुरू करने की दिशा में सचिवीय कानून और फ़टब के तहत अंडरटेकिंग अनुपालन

T + 270	<ul style="list-style-type: none"> स्वैच्छिक परिसमापन और परिसमापक की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों के प्रस्ताव को पारित करना
T + 300	<ul style="list-style-type: none"> आयकर, RoC, IBBI, GST अधिकारियों और PF विभाग को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू करने और परिसमापक की नियुक्ति के बारे में सूचित करना। दावों को आमंत्रित करने वाले अखबारों में सार्वजनिक घोषणा नकदी और तरल निधियों के लिए एक नामित बैंक खाता खोलना मौजूदा बैंक खाते को बंद करना और नामित बैंक खाते में धनराशि का स्थानांतरण
T + 315	<ul style="list-style-type: none"> कॉर्पोरेट देनदार के शेयरधारकों को प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना
T + 315 to T + 1350	<p>आयकर¹</p> <ul style="list-style-type: none"> चल रही और नए मूल्यांकन की कार्यवाही को पूरा करना, अपीलीय मुकदमेबाजी और एक साथ विभिन्न नोटिसों पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना। टैक्स एनओसी प्राप्त करने के लिए आयकर अधिकारियों के साथ कॉर्पोरेट देनदार के प्रमुख शेयरधारक से एक बैंक गारंटी को प्रस्तुत करना। <p>भविष्य निधि (PF)²</p> <ul style="list-style-type: none"> क्षेत्रीय PF अधिकारियों के साथ स्थापना के EPF खाते को बंद करने के लिए दायर करना <p>GST पंजीकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> समय-समय पर वैधानिक अनुपालन (रिवर्स चार्ज और रिटर्न फाइलिंग के तहत कर का भुगतान) स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में जीएसटी पंजीकरण का समर्पण <p>विदेशी मुद्रा कानून*</p> <ul style="list-style-type: none"> शेयरधारकों को अंतिम प्रेषण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के लिए अधिकृत डीलर बैंक के साथ चर्चा के समय विदेशी मुद्रा कानूनों के तहत रिपोर्ट करना। <p>पूर्व कर्मचारियों से संचार और परिचालन क्रेडिट से दावे</p> <ul style="list-style-type: none"> कंपनी के पूर्व कर्मचारियों के च्च पोर्टल से बार-बार अनुरोध परिचालनात्मक लेनदारों के दावे परिसमापन शुरू होने की तारीख से 30-दिन की दावा अवधि के बाद होते हैं <p>सरकारी निकायों से सुरक्षा जमा</p> <ul style="list-style-type: none"> पंजीकरण के समय कॉर्पोरेट देनदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि की वापसी/सरकारी निकायों के साथ लाइसेंस प्राप्त करना
T + 1350 to T + 1360	<ul style="list-style-type: none"> शेयरधारकों को अंतिम प्रेषण और लागू रोक के कर्तव्यों को जमा करना, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया का समापन नामित बैंक खाता बंद करना
T + 1360 to T + 1370	<ul style="list-style-type: none"> शेयरधारकों, RoC, IBBI और NCLT को अंतिम रिपोर्ट सौंपना (विघटन याचिका के साथ) NCLT के साथ कॉर्पोरेट देनदारों के विघटन के साथ आवेदन दाखिल करना
T + 1430	<ul style="list-style-type: none"> NCLT की पहली सुनवाई की निर्धारित तिथि NCLT का आदेश आयकर विभाग, RoC और IBBI से रिपोर्ट/जवाब मांगता है

¹कॉर्पोरेट देनदार के प्रमुख शेयरधारक से बैंक गारंटी आयकर अधिकारियों से सुसज्जित थी और सूचना के दाखिल से 1000 दिनों के बाद कर एनओसी प्राप्त की गई थी।

²PF अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्यवाही < 370 दिनों में संपन्न हुई और बाद में, PF की कमी के भुगतान पर ब्याज और हर्जाने के संबंध में जांच शुरू की गई, अगले < 300 दिनों में समाप्त कर दी गई।

T + 1430 to T + 1515	<ul style="list-style-type: none"> आयकर विभाग, RoC और IBBI के साथ अनुवर्ती, NCLT आदेश की प्राप्ति की पुष्टि करें और उनकी समय पर प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध करें संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए गए पते के प्रश्न
T + 1515	<ul style="list-style-type: none"> NCLT की दूसरी सुनवाई की निर्धारित तिथि आयकर विभाग, RoC और IBBI से रिपोर्ट/उत्तर रिकॉर्ड में लाएँ
T + 1515 to T + 1540	<ul style="list-style-type: none"> आयकर विभाग, RoC और IBBI द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/उत्तरों की संतुष्टि के अधीन, कॉर्पोरेट देनदार को भंग करने का आदेश पारित करें।
T + 1540 to T + 1570	<ul style="list-style-type: none"> आरओसी के साथ कॉर्पोरेट देनदार के विघटन के लिए आदेश की फाइल कॉपी फॉर्म INC 28 कंपनियों के रजिस्टर से कॉर्पोरेट देनदार के नाम काट देने के लिए RoC

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण के लिए QCI अध्ययन

नोट: ' प्रक्रिया केवल विदेशी कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी के मामले में लागू होती है।

अपूर्ण नियमों की अनिवार्यता

6.7 अति नियमन की समस्या अनिश्चितता की दुनिया में अधूरे अनुबंधों और नियमों की अनिवार्यता को मान्यता नहीं देने से उपजी है। वास्तविक दुनिया के अनुबंध तीन प्रमुख कारणों से स्वाभाविक रूप से अपूर्ण हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को सुदृढ़ करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हर्बर्ट साइमन ने अपने नोबेल-पुरस्कार जीतने के काम में प्रकाश डाला है, मनुष्य तेजी से तर्कसंगत है क्योंकि भविष्य में “अज्ञात अज्ञात” शामिल हैं। ध्यान दें कि “अज्ञात अज्ञात” की मौलिक अनिश्चितता फ्रैंक नाइट द्वारा परिभाषित जोखिम की धारणा से मौलिक रूप से अलग है। दूसरा, ओलिवर हार्ट द्वारा किए गए अधूरे अनुबंधों पर एक और नोबेल-पुरस्कार विजेता काम के रूप में, अनुबंधित अनुबंधों में जटिलता सभी संभावित आकस्मिकताओं के पार सभी पक्षों के लिए सभी दायित्वों की प्रत्याशा और निर्दिष्ट करने में शामिल कठिनाइयों से उत्पन्न होती है। वास्तव में, कट्टरपंथी अनिश्चितता के साथ, दुनिया के सभी भविष्य के राज्यों की संभावित विशेषताओं को जानना असंभव है। इसलिए, संपूर्ण अनुबंधों को लिखना जो हर भविष्य की स्थिति को कुशलतापूर्वक फिट करना वास्तविक दुनिया में स्वाभाविक रूप से असंभव है। अंत में, इन दो विशेषताओं के कारण, एक तृतीय पक्ष पूर्व पद के परिणामों का निरीक्षण करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन पूर्व-पूर्व के निर्णयों को अनायास सत्यापित नहीं कर सकता है।

6.8 अधूरे अनुबंधों की वास्तविकता को स्वीकार किए जाने पर अपूर्ण नियम अपरिहार्य हो जाते हैं। सिद्धांत रूप में, नियामक और नीति निर्धारक पूरी तरह से दुनिया की हर संभव स्थिति की पहचान करके और प्रत्येक राज्य के लिए एक उपयुक्त समाधान निर्दिष्ट करके मसौदा प्रक्रिया में निवेश करना चुन सकते हैं। लेकिन, वास्तव में, वे एक विकराल समस्या का सामना करते हैं: भविष्य अज्ञात और अनजाना है। नतीजतन, जब अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, तो बस बहुत अधिक लागत आती है और फिर दुनिया के बोधगम्य राज्यों के सभी (या यहां तक कि सबसे) के लिए उचित रूप से अनुबंध के परिणामों का वर्णन करता है। इस प्रकार, अपूर्ण अनुबंधों की वास्तविकता अधूरा विनियमन की अनिवार्यता की ओर ले जाती है। यह कुछ विवेकाधिकार को अपरिहार्य बनाता है।

6.9 एक जटिल और अनिश्चित दुनिया में, इसके अलावा, वास्तविक परिणाम या स्थितियां विनियमन में ग्रहण किए गए स्वच्छ बक्से में फिट नहीं होती हैं; इसलिए पर्यवेक्षक को कुछ निर्णय लेने होंगे। ऐसी स्थितियों में, जटिल नियम और नियम कई तरीकों के कारण अधिक विवेक पैदा करते हैं, जिसमें उनकी व्याख्या की जा

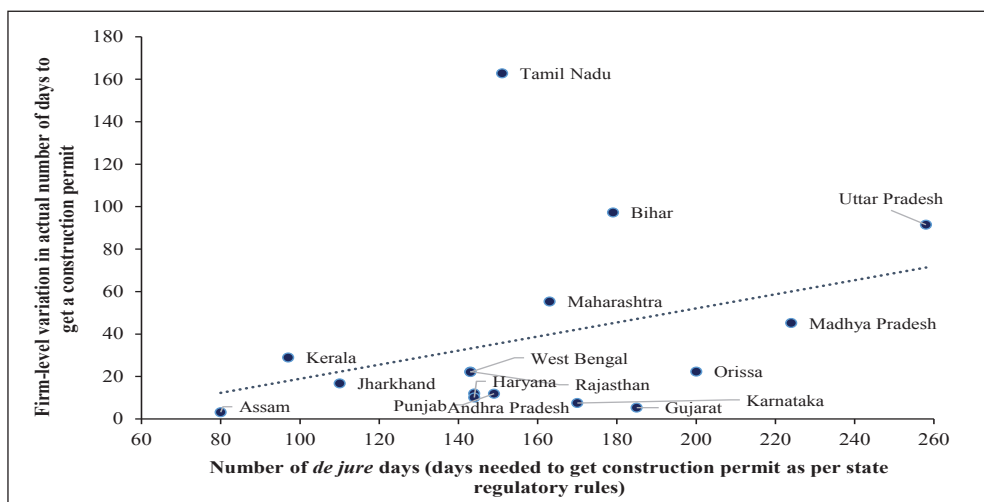
सकती है। यह इस तथ्य से भी बदतर बना है कि तेजी से जटिल नियमों की अस्पष्टता तीसरे पक्ष के लिए यह निगरानी करना मुश्किल बनाती है कि विवेक कैसे बहिष्कृत किया गया था। ब्लैक (2001) का तर्क है कि “विवेक और नियम शून्य-योग संबंध में नहीं हैं, जैसे कि जितने अधिक नियम हैं उतने ही कम विवेक हैं और वीजा-वर्सा है।” विवेक का ऐसा अभ्यास स्वाभाविक रूप से अपारदर्शी है और किराए पर लेने के लिए अवसर पैदा करता है। इस प्रकार, अति-विनियमन, सरल विनियमन नहीं, अत्यधिक और अपारदर्शी विवेक की ओर जाता है।

अति-नियमन के साथ विवेक में वृद्धि का समर्थन करने वाले साक्ष्य

6.10 उनकी पुस्तक में “इन रेग्युलेटिंग एजेड केयर: रिचुअल एंड द न्यू पिरामिड”, Braithwaite et.al. (2007) संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का अध्ययन करें और सबूत प्रदान करें जो उपरोक्त थीसिस के अनुरूप है। पुस्तक बुजुर्गों की देखभाल को विनियमित करने के प्रभाव पर केंद्रित है। यह तर्क दिया गया था कि वृद्ध देखभाल घरों में काम करने वाले निरीक्षकों में बहुत अधिक विवेक था। इस परिदृश्य को बदलने और अपने विवेक को कम करने के लिए, निरीक्षकों को ऑडिट करने के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल प्रदान किए गए थे। इन मानकों को उप-मानकों में तोड़ दिया गया था और 500 से अधिक संघीय मानकों तक पहुंच गया था, जो 1986 तक कुछ राज्य के विशिष्ट मानकों के पूरक थे। उदाहरण के लिए, नर्सिंग के लिए इलिनोइस कोड में 5,000 से अधिक देखभाल नियम शामिल थे। ऊपर लिखी गई तर्कसंगतता के अनुरूप, लेखकों ने पाया कि निरीक्षक इन मानकों की संख्या में वृद्धि के साथ सामना नहीं कर सके। इनमें से अधिकांश मानकों को पूरी तरह से भुला दिया गया था और मानकों को बनाने के लिए केवल 10 प्रतिशत मानकों का बार-बार उपयोग किया गया था। अध्ययन ने नोट किया कि परिणाम निरीक्षकों की पृष्ठभूमि पर निर्भर थे, जैसे कि “यदि आपको एक नर्स मिली है, तो यह सर्वेक्षण रिपोर्ट में नर्सिंग कमियाँ होगी; यदि कोई फार्मासिस्ट है, तो आपको फार्मसी कमियाँ मिलेगी; एक वकील, रोगी अधिकार, आदि” नियमों का जटिल समूह, वास्तव में, निरीक्षक को अधिक विवेक देता है। जांच करने के लिए जटिल और बड़ी संख्या में मानकों के कारण, निरीक्षक की संकीर्ण विशेषज्ञता से जुड़े अज्ञात कारक कुछ घरों में विशेष मानकों की जांच करने का कारण बने, लेकिन दूसरों में उपेक्षित हैं। इस प्रकार, अति-विनियमन ने स्थानिक अनिश्चितता का कारण बना और विस्तृत विनियमों के पूरे उद्देश्य को पराजित किया। बिना किसी मुकदमे/विवाद के एक साफ कंपनी को बंद करने से जुड़ी समयरेखा, जो ऊपर तालिका 3 में वर्णित है, इस समस्या का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है।

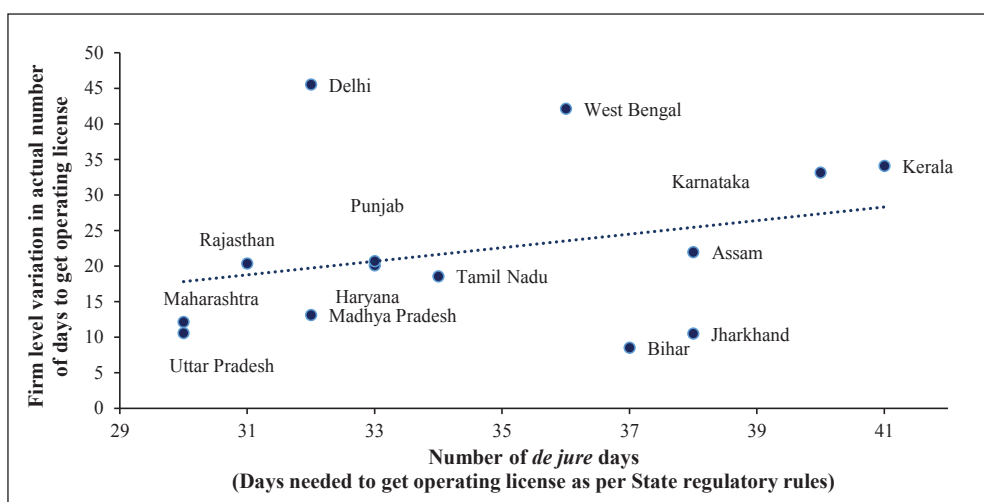
6.11 इसी तरह, चित्र 3 और 4 भारतीय राज्यों में बड़े नमूना सबूत प्रदान करते हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि विनियमन की मात्रा के साथ विवेक बढ़ता है। साक्ष्य राज एट अल से अनुकूलित है। (2018) जो भारत के विश्लेषण के लिए विश्व बैंक के उद्यम स्तर का सर्वेक्षण करते हैं। चित्र 3 में, निर्माण परमिट प्रदान करने के लिए लिए गए निर्माण की अनुमति के कार्य के रूप में निर्माण परमिट प्रदान करने के लिए ली गई वास्तविक दिनों में फर्मों के बीच भिन्नता, राज्य में समान के लिए नियामक नियमों के अनुसार प्लॉट किए जाते हैं। हम देखते हैं कि नियमों की संख्या में वृद्धि, जो परमिट प्राप्त करने के लिए de jure दिनों में वृद्धि से अनुमानित है, लिया गया दिनों की वास्तविक संख्या में भिन्नता के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधी है। जैसा कि डी ज्यूर के मानदंड के विरुद्ध भिन्नता फर्मों से विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोग किए गए विवेक का अनुमान लगाती है, यह दर्शाता है कि निर्माण परमिट के पुरस्कार के मामले में विनियमों की संख्या, उन्हें लागू करने में अधिक विवेक। चित्र 4 एक सुविधा के लिए एक ऑपरेटिंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए लिए गए दिनों का उपयोग करके समान दिखाता है। सामूहिक रूप से, ये दोनों आंकड़े थीसिस के अनुरूप सबूत प्रदान करते हैं कि नियमों की संख्या के साथ विवेक बढ़ता है।?

चित्र 3: निर्माण की अनुमति देने में विवेकाधिकार de jure के प्रावधानों के साथ बढ़ता है



स्रोत: Raj et al (2018); फर्म स्तर भिन्नता को मानक विचलन द्वारा मापा जाता है; उच्च भिन्नता उच्च विवेक का अनुमान लगाती है

चित्र 4: de jure प्रावधानों के साथ ऑपरेटिंग लाइसेंस देने में विवेक बढ़ता है



स्रोत: Raj et al (2018); फर्म स्तर भिन्नता को मानक विचलन द्वारा मापा जाता है

6.12 Kanbur और Ronconi (2016) श्रम कानूनों पर अपने क्रॉस-कंट्री अध्ययन में दिखाते हैं कि श्रम विनियमन की कठोरता (न्यूनतम वेतन के उल्लंघन के लिए ठीक है) इसके प्रवर्तन की तीव्रता के साथ नकारात्मक रूप से संबद्ध है (औसत मध्यम कारावास के रूप में मापा जाता है)। उनका तर्क है कि अधिक कठोर श्रम संहिता वाले देशों में उन्हें लागू करने की संभावना कम है।

6.13 अंत में, उपरोक्त थीसिस का एक और चित्रण संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अधिनियमित किए गए Dodd&Frank Act है, जिसमें 848 पृष्ठ और 390 नए नियम अनिवार्य हैं। यह 2008 के संकट की ओर ले जाने वाले वर्षों में जो कुछ गलत हुआ उसे ठीक करने का एक सुविचारित प्रयास था। कोई यह सोच सकता है कि नियामकों को अपने विवेक का उपयोग करने के लिए यह थोड़ा बचा है। वास्तव में, जो हुआ वह काफी विपरीत था। पेट्रो (2012) ने तर्क दिया कि डोड-फ्रैंक ने एक नए तरह का जोखिम पैदा किया, जिसे उसने “जटिलता जोविम” का नाम दिया। उदाहरण के लिए, कानून में 184 अतिरिक्त गतिविधियों

के लिए बैंक बोर्डों को जिम्मेदार होना चाहिए, जो अनावश्यक हो सकता है - या असंभव भी हो सकता है।

6.14 इससे पता चलता है कि अधिक कठोर नियमन होने का मतलब वास्तव में यह हो सकता है कि कारण पर विवेक का प्रयोग अधिक होता है, कम नहीं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अनिश्चितता और जटिलता से भरी दुनिया में, अधिक प्रिस्क्रिप्टिव विनियमन के साथ प्रभावी पर्यवेक्षण को प्रतिस्थापित करना संभव नहीं है। ध्यान दें कि तृतीय-पक्ष पर्यवेक्षण को नियोजित करने से अपारदर्शी विवेक के लिए विनियमन को सरल बनाने की प्रक्रिया को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुबंध के अधूरे होने पर किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा प्रयासों और कार्यों की सत्यता से ऊपर तर्क दिया जाता है। इसलिए, फिर सवाल यह उठता है कि हम ऐसे विवेक की अनुमति कैसे दे सकते हैं जिसका दुरुपयोग न हो और प्रभावी पर्यवेक्षण हो।

नियामक डिफॉल्ट की समस्या

6.15 पिछले अनुभागों में चर्चा से, यह स्पष्ट है कि पर्यवेक्षक को लचीलापन और विवेक प्रदान करके सरल विनियमन बनाने और उसी को पूरक करने की आवश्यकता है। हालाँकि, यदि कानूनी और संस्थागत ढांचे स्पष्ट रूप से नियमों के पालन-पोषण को सीमित नहीं करते हैं, तो नीति-निर्माता स्वाभाविक रूप से अधिक विनियमन की ओर बढ़ सकते हैं, भले ही यह अर्थव्यवस्था के लिए उप-इष्टतम हो। प्रिंसिपल-एजेंट की समस्या का विश्लेषण करते हुए, Holstorm & Milgrom (1979) का तर्क है कि बहु-आयामी कार्य दुनिया में सर्वव्यापी हैं और एजेंटों को विभिन्न कर्तव्यों के बीच अपना समय विभाजित करना होगा। ऐसे मामलों में, एजेंट उन कार्यों का चयन करते हैं जिनके परिणाम औसत दर्जे के होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि छात्रों के परीक्षा के अंकों के आधार पर शिक्षकों के लिए एक प्रोत्साहन वेतन है, तो शिक्षक संकीर्ण रूप से परिभाषित बुनियादी कौशल पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो मानकीकृत परीक्षणों पर परीक्षण किए जाते हैं न कि छात्र सीखने के विभिन्न पहलुओं पर। प्रभावी रूप से, वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि प्रभावी रूप से मापा क्या जा सकता है। इसी तरह, चूंकि विनियमन को आसानी से मापा जा सकता है, जबकि पर्यवेक्षण को आसानी से नहीं मापा जा सकता है, नियामक और निर्णय-निर्माता पर्यवेक्षण को अधिक से अधिक विनियमन के साथ प्रतिस्थापित करना पसंद करेंगे। आखिरकार, नियम मानदंड या चेकलिस्ट प्रदान करते हैं, जिससे नियामकों के लिए बाद में उनकी जवाबदेही का पालन करना और कम करना आसान हो जाता है। दूसरी ओर, पर्यवेक्षण की मात्रा और गुणवत्ता को निर्धारित करना मुश्किल है। स्वाभाविक रूप से, नीति-नियंता डिफॉल्ट रूप से प्रिस्क्रिप्टिव विनियमन का पक्ष लेते हैं। यह उनकी प्रभावशीलता की परवाह किए बिना अधिक ऊपर से नीचे नियमों को जोड़ने के लिए एक विकृत प्रोत्साहन बनाता है। निम्नलिखित अनुभाग इस पर विस्तार से चर्चा करता है।

(क) इसकी प्रभावशीलता की परवाह किए बिना समय के साथ अधिक विनियमन जोड़ा जाता है

6.16 चूंकि विनियमन एक अधिक यांत्रिक, ऊपर से नीचे दृष्टिकोण है, यह अक्सर नीति निर्माताओं की डिफॉल्ट प्रतिक्रिया बन जाती है। इसने पहले अति विनियमित की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, बाद में प्रश्न पूछें। '(ऑस्ट्रेलियाई सरकार के कार्यबल की रिपोर्ट, 2006)

6.17 ऐसे कई उदाहरण भारत में विपुल हैं। वाणिज्य मंत्रालय की उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह की रिपोर्ट (2019) ने निधियों के 'राउंड-ट्रिपिंग' को रोकने के लिए जटिल और कड़े नियमों की एक भूलभुलैया का उल्लेख किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि report राउंड-ट्रिपिंग के सामान का उपयोग वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र को किसी भी राजमार्ग के निर्माण को रोकने के लिए यातायात दुर्घटना के जोखिम का उपयोग करने से अधिक करने के लिए नहीं किया जा सकता है। एक और उदाहरण कभी-कभी बढ़ते बैंक नियमों का अनपेक्षित परिणाम है जिसके कारण बाजार गतिविधि को "छाया बैंकों" (जिसे "गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ" भी कहा जाता है) में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां विनियामक मध्यस्थता की गुंजाइश अधिक है, खासकर जब बैंक अधिक हो जाते हैं उच्च-जोखिम वाले उधारकर्ताओं और/या छोटे उधारकर्ताओं को उधार देने के लिए। वित्तीय

प्रणाली के एक हिस्से में बढ़ते विनियमन ने जोखिम को वित्तीय प्रणाली के कम-पारदर्शी, कम पारदर्शी हिस्से में स्थानांतरित कर दिया है (Sanyal, 2020)।

(ख) ऐसा करने का मामला होने पर भी विवेक प्रदान नहीं किया जाता है या उपयोग/प्रयोग नहीं किया जाता है

6.18 चूंकि नियमों को परिभाषित किया गया है, इसलिए उनको घटना से पहले मापना आसान है। नौकरशाही स्वाभाविक रूप से यांत्रिक नियमों के साथ पर्यवेक्षण को प्रतिस्थापित करेगी और उपलब्ध होने पर भी विवेक का प्रयोग नहीं करेगी।

6.19 चित्रण के रूप में, सार्वजनिक खरीद का मामला लें। सामान्य वित्तीय नियमों (GFRs) के दिशानिर्देशों के अनुसार, न्यूनतम लागत विधि, या आमतौर पर 1 L1 'सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो कि सामान्य/निर्माण और गैर-परामर्शी सेवाओं के लिए सबसे प्रचलित बोली पद्धति है।

6.20 एक सामान्य समझौता है कि पूरी तरह से एल 1 पर निर्भर रहने से अच्छा काम नहीं होता है और विभिन्न संगठनों ने पिछले कुछ वर्षों में वर्तमान खरीद प्रणाली में सुधार की आवश्यकता की वकालत की है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपने कॉन्सेप्ट नोट में काम और माल अनुबंध के पुरस्कार के लिए वैकल्पिक खरीद रणनीति पर ध्यान दिया कि यद्यपि L1 अभी भी नियमित कार्यों, वस्तुओं और गैर-परामर्श सेवाओं की खरीद के लिए अच्छा हो सकता है; लेकिन उच्च प्रभाव और तकनीकी रूप से जटिल खरीद के लिए नहीं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) ने राजमार्ग विकास क्षेत्र पर एक अध्ययन किया और पाया कि जिन विक्रेताओं को प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर सभी अनुबंधों से सम्मानित किया गया था, वे काम की गुणवत्ता और प्रदर्शन के मामले में व्यापक रूप से भिन्न हैं जो मौजूदा बोली मूल्यांकन प्रणाली के तहत कवर नहीं किए गए थे। रिपोर्ट ने प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया में प्रदर्शन रेटिंग को शामिल करने का सुझाव दिया, जो कि बेहतर बोली लगाने वाले को एक गुणवत्ता प्रीमियम प्रदान करने के बजाय L1 बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करता है और वित्तीय स्कोर और प्रदर्शन रेटिंग स्कोर के योग के रूप में कुल स्कोर की गणना करने के लिए एक सूत्र दिया। NITI Aayog कॉन्सेप्ट पेपर में Pro इंडियन पब्लिक प्रोक्योरमेंट: ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी एंड वे फॉरवर्ड 'का तर्क है कि L1 सभी परिदृश्यों में उपयुक्त नहीं है और खरीद प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए कई प्रकार के विकल्प के साथ आया है। वास्तव में, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे मल्टीलेटरल के नए प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क में मौजूदा समय में बदलाव और सुधारों की जरूरतों की ओर इशारा करते बोलीदाताओं का चयन करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक रणनीति है। वे 'एक आकार सभी के लिए फिट बैठता है' उद्देश्य के लिए 'फिट' दृष्टिकोण विचलित हैं और खरीद के तरीकों में गैर-मूल्य विशेषताओं आदि पर विचार करने के लिए वैल्यू फॉर मनी, रेटेड मानदंड जैसे विभिन्न विकल्पों को शामिल किया है।

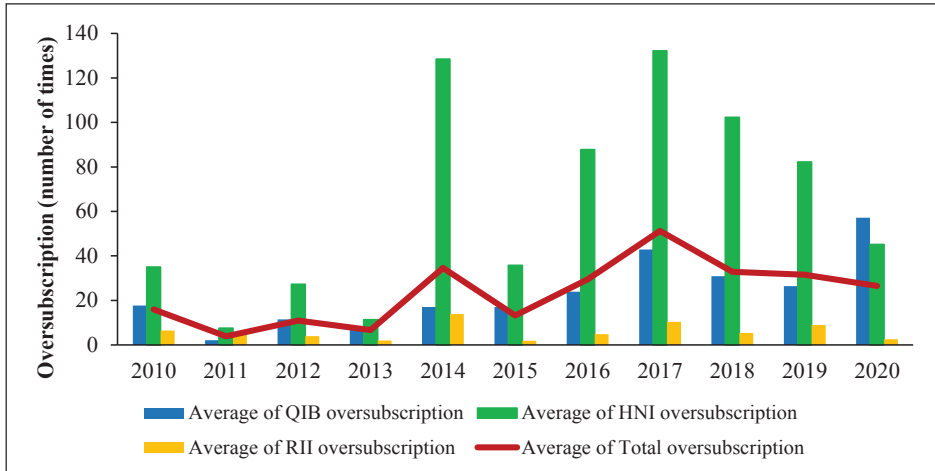
6.21 तकनीकी और गुणवत्ता आधारित मापदंडों के आधार पर बोली प्रक्रिया में और अधिक विवेक की अनुमति देने की आवश्यकता की सिफारिश करने के बावजूद, हम अभी भी ज्यादातर L1 का उपयोग करते हैं। L1 प्रणाली नियामक डिफॉल्ट समस्या के कारण बनी रहती है। भविष्य की पूछताछ के डर से कोई भी निर्णय लेने वाला विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहता। यह मानदंड सरल और मात्रात्मक दिखाई दे सकता है, हालांकि, एक जटिल दुनिया में जहां पूर्व-खरीद प्रक्रिया में सब कुछ परिभाषित करना संभव नहीं हो सकता है, पर्याप्त पारदर्शिता और सक्रिय पर्यवेक्षण बनाए रखने के साथ-साथ प्रशासकों के हाथों में कुछ विवेक छोड़ना उचित है।

(ग) विवेक के लाभ के साथ विवेक पर सवाल उठाया जाता है

6.22 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) में घटना से पहले का विवेक अक्सर आईपीओ की निगरानी और/या पहले दिन का लाभ बढ़ा होने पर बाधा के लाभ के साथ पूछताछ की जाती है। हालांकि, एक असूचीबद्ध इकाई का बाजार मूल्य अज्ञात है। मूल्यांकन तकनीक, प्रयास और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग

के बाद भी, एक इकाई का वास्तविक मूल्य अनिश्चित है जब तक कि यह बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है। शेयरों को ओवर-सब्सक्राइब (या अंडर-सब्सक्राइब) होना और उनकी कीमतें बढ़ना (या नीचे) देखना असामान्य नहीं है। जैसा कि आंकड़े 6 और 7 दिखाते हैं, निजी क्षेत्र में आईपीओ के लिए ओवरसब्सक्रिप्शन और महत्वपूर्ण पहले दिन के लाभ कई वर्षों में काफी महत्वपूर्ण हैं; उसी समय, लिस्टिंग मूल्य की भविष्यवाणी में शामिल अनिश्चितता को दर्शाते हुए, कुछ वर्षों में नुकसान बहुत बड़े हैं। चित्र 6 बीएसई और एनएसई पर 2010-2020 के बीच सूचीबद्ध भारतीय आईपीओ के शेयरों की संख्या को अलग-अलग निवेशकों द्वारा देखा गया। पिछले 5 वर्षों में, इन आईपीओ के लिए औसत कुल सदस्यता 20-40 गुना रही है, हालांकि पिछले वर्षों में यह कम रही है। चित्र 7 से पता चलता है कि पिछले 7-8 वर्षों में अधिकांश निजी क्षेत्र के आईपीओ को सकारात्मक लिस्टिंग का लाभ मिला है, हालांकि पिछले वर्षों में नुकसान बहुत बड़े हैं। 2019 में भी, लगभग 60 प्रतिशत आईपीओ में सकारात्मक लिस्टिंग लाभ था। तालिका 6 कुछ विशिष्ट शेयरों की जानकारी को इस बिंदु पर सूचीबद्ध करने के लिए सूचीबद्ध करती है कि अपेक्षित लिस्टिंग मूल्य और सदस्यता की मात्रा एक प्राथमिकताओं के लिए काफी अनिश्चित है।

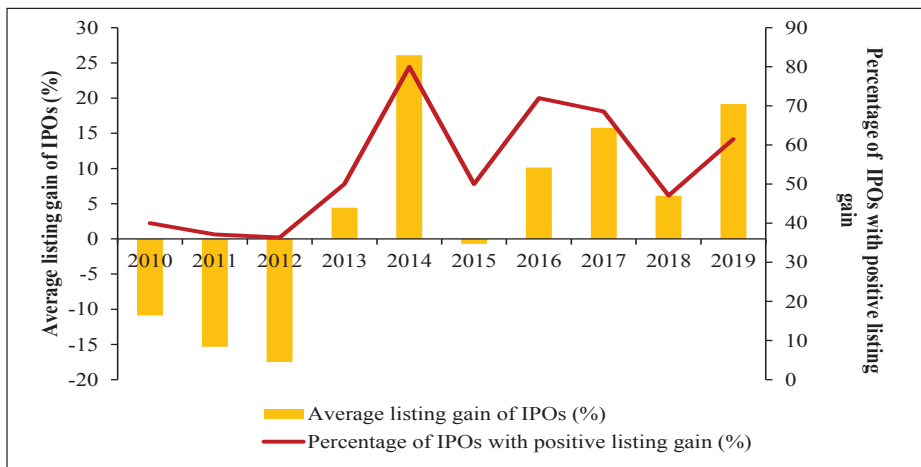
चित्र 6: बीएसई और एनएसई (2010-20) में सूचीबद्ध भारतीय आईपीओ का ओवर सब्सक्रिप्शन



स्रोत: बीएसई और एनएसई नोट: 2007 के बाद सूचीबद्ध सभी भारतीय आईपीओ स्टॉक कवर किए गए हैं।

QIB: योग्य संस्थागत खरीदार; एनआईआई: उच्च नेट-वर्थ व्यक्तिगत निवेशक; आरआईआई: खुदरा व्यक्तिगत निवेशक; कुल ओवर सब्सक्रिप्शन: टाइम्स इश्यू की संख्या सब्सक्राइब्ड (BSE + NSE)

चित्र 6: बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध भारतीय आईपीओ की सूची (2010-19)



स्रोत: बीएसई और एनएसई

नोट: 2007 के बाद सूचीबद्ध सभी भारतीय आईपीओ स्टॉक कवर किए गए हैं।

तालिका 4: बाजार में सूचीबद्ध शेयरों की कीमतें खोलना और बंद करना

कंपनी	लिस्टिंग की तारीख	सब्सक्रिप्शन (समय की संख्या)	आईपीओ मूल्य (₹)	बंद कीमत (₹)	प्रतिफल (%)
Burger King India	2 दिसम्बर 2020	1.84	60	138.4	131
SBI Card	5 मार्च 2020	26.5	755	730	-4
Ujjivan FSB	12 दिसम्बर 2019	166	37	58	56.76
CBS Bank	4 दिसम्बर 2019	87	195	274.25	40.64
IRCTC	3 अक्टूबर 2019	112	320	874	173
Sterling & Wilson Solar	6 अगस्त 2019	0.85	780	273.1	-65
Affle (India)	31 जुलाई 2019	86	745	1470	97.3
India Mart InterMesh	26 जून 2019	36	973	2131	119
Neogen Chem	26 अप्रैल 2019	41	215	358	66.5
Polycab India	9 अप्रैल 2019	52	538	1016.2	88.88
Metropolis Healthcare	6 अप्रैल 2019	6	880	1350	53.41

स्रोत: BSE

नोट: लिस्टिंग के पहले दिन बंद कीमत

6.23 ऐसे मामलों में जब सरकारी संस्थाएं सार्वजनिक हो जाती हैं और बाजार में स्टॉक सूचीबद्ध होने के बाद कीमतें बढ़ती हैं, तो यह महसूस किया जाता है कि संपत्ति बहुत अधिक मूल्य की थी। टिप्पणीकार तब 'पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह' की टिप्पणी के साथ कि संपत्ति बहुत सस्ती बेची गई थी। हालांकि, कीमतें सूचीबद्ध होने के बाद ही और शेयरों को द्वितीयक बाजार में कारोबार किया जाता है, वास्तविक मूल्यांकन ज्ञात है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अद्वितीय नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र में भी होता है। न केवल विभिन्न आईपीओ ओवर-सब्सक्राइब किए गए हैं, बल्कि लिस्टिंग के दिन नजदीकी कीमत आईपीओ मूल्य (तालिका 4) से काफी अलग है।

(घ) सरकारी विभाग डिफॉल्ट मिसाल का पालन करते हैं

6.24 सरकारी विभाग विनियमन की जांच सूची में बक्सों पर टिक करने के लिए या डिफॉल्ट मिसाल का पालन करने के लिए कार्रवाई करते हैं। इस प्रकार, हम बाद में किसी भी प्रश्न को कम करने के लिए उच्च न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में प्रतिकूल निर्णयों के खिलाफ सरकारी विभागों द्वारा की गई नियमित अपील देखते हैं।

6.25 भारत में, कर-संबंधी मामलों में किसी भी विवाद को हल करने की एक बहुस्तरीय प्रणाली है। जांच के बाद, विभाग या आकलन के पास आयकर अपीलों (CIT-A), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (ITAT), उच्च न्यायालयों (HC) और अंत में भारत के सुप्रीम कोर्ट (SC) के पास आने का विकल्प है। प्रत्यक्ष कर में विवादों के मामले में। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में गणना के अनुसार, विभाग की अपीलों प्रत्यक्ष करों के मामले में दायर अपील की कुल संख्या का लगभग 85 प्रतिशत है। मार्च 2017 को समाप्त तिमाही तक लंबित प्रत्यक्ष कर मामलों की कुल संख्या में से, विभाग ने आईटीएटी और उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी के 88 प्रतिशत के करीब और उच्च न्यायालयों में लंबित 83 प्रतिशत मुकदमें शुरू किए। हालांकि, विभाग सुप्रीम कोर्ट और आईटीएटी में 73 प्रतिशत और उच्च न्यायालय (तालिका 5) में 87 प्रतिशत मामले खो देता है। भले ही

सरकार द्वारा मुकदमेबाजी की सफलता की दर बहुत कम हो, लेकिन उच्च अधिकारियों से अपील करने के लिए नीति निर्माताओं के बीच एक प्रवृत्ति है।

तालिका 5: याचिका दर और प्रत्यक्ष करों की सफलता दर (प्रतिशत में)

कोर्ट/ट्रिब्यूनल	याचिका दर	सफलता दर
उच्चतम न्यायालय	87	27
उच्च न्यायालय	83	13
ITAT	88*	27

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 गणना

नोट: *अनंतिम अनुमान

विवेक के लिए हल

6.26 उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट होना चाहिए कि सक्रिय पर्यवेक्षण और विवेक का कोई विकल्प नहीं है। विशेष रूप से, पूर्व-पोस्ट विनियमन पूर्व पोस्ट पर्यवेक्षण के लिए स्थानापन्न नहीं कर सकते हैं; वास्तव में, अधिक घटनाओं से पहले विनियमन केवल अपारदर्शी विवेक को बढ़ावा देकर पूर्व पोस्ट पर्यवेक्षण की गुणवत्ता को पतला करने का कार्य करता है। तो, उन्हें विवेक देते हुए पर्यवेक्षकों को कैसे जवाबदेह रखा जा सकता है? हम तीन संभावित तरीके तलाशते हैं:

(क) घटनाओं से पहले की जवाबदेही को मजबूत करें

6.27 अधूरे अनुबंधों के आधार पर संपत्ति अधिकार साहित्य संस्थानों में शासन की मजबूती के लिए तर्क देता है कि बोर्ड में अधिक शक्ति निहित है और फिर उन्हें जवाबदेह घटनाओं से पहले को रखा जाता है। पूर्व-पोस्ट ऑडिट पर बहुत अधिक भरोसा करने के बजाय, जो वैसे भी पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं, घटनाओं से पहले जवाबदेही को संस्थानों के बोर्ड के साथ सौंपा जाना चाहिए। अधिकांश सामान्य कानून देशों में, एक मामला कानून है जिसे ब्यूनेस जजमेंट रूल का सिद्धांत माना जाता है। नियम में कहा गया है कि बोर्डों को अच्छे विश्वास के साथ काम करने के लिए माना जाता है और कंपनियों को यह मानते हुए भड़काऊ मुकदमों से बचाता है कि जब तक अन्यथा साबित नहीं किया जाता है, प्रबंधन शेरधारकों के हितों में काम कर रहा है। यह भारत में भी मौजूद है, हालांकि एक ही भाषा में बिल्कुल संहिताबद्ध नहीं है। लेकिन इस बात की काफी आशंका है कि ऑडिट और कार्यांतर/पोस्ट-फैक्टो की जांच में इस पर ध्यान न दिया जाए।

(ख) निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएं

6.28 प्रभावी पर्यवेक्षण की दिशा में दूसरा तरीका निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को शामिल करना है। पारदर्शिता, आंतरिक मूल्य होने के अलावा, इसकी सराहना की जाती है क्योंकि यह सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को बढ़ावा देता है और बाजार को कुशल बनाता है। निर्णय लेने में पारदर्शिता के साथ प्रणाली में विवेक को संतुलित करने की आवश्यकता है।

6.29 सार्वजनिक खरीद में हालिया सुधार से पारदर्शिता का लाभ देखा जा सकता है। सरकार ने 2016 में सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा खरीदे या बेचे जाने वाले विभिन्न सामानों और सेवाओं के लिए सरकारी ई मार्केटप्लेस (GeM) के रूप में जाना जाता है। वास्तविक प्रमाण बताते हैं कि GeM से पहले, सरकारी खरीद मूल्य बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में बहुत अधिक थे और अक्षमता और किराए की मांग के बारे में लगातार शिकायतें थीं। जीईएम वेबसाइट का उल्लेख है कि इस ई-मार्केटप्लेस के उपयोग से निविदा, दर

अनुबंध और प्रत्यक्ष खरीद दरों की तुलना में कीमतों में काफी कमी आई है जो पहले उपयोग किए गए थे। GeM पर औसत मूल्य कम से कम 15-20 प्रतिशत है, और कुछ मामलों में 56 प्रतिशत तक भी कम है।

6.30 कंपनी वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, Flipkart, आदि के साथ GeM पोर्टल पर विभिन्न वस्तुओं की कीमतों की तुलना नीचे दी गई तालिका (तालिका 6) में दी गई है। अध्ययन (4 जनवरी, 2021 को किए गए) के लिए, सामान्य वस्तुओं के एक सेट की पहचान की गई थी। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि उत्पादों का यथासंभव निकट से मिलान किया जाए। अध्ययन में कीमतों का एक ही बॉलपार्क में होना पाया गया। औसतन, GeM और अन्य ऑनलाइन बाजार स्थानों पर कीमतों के बीच का अंतर केवल 3 प्रतिशत है। एक खुला मंच सतर्क नागरिक होने के नाते यह वास्तविक समय की निगरानी करना जारी रख सकता है।

तालिका 6: जीईएम पोर्टल मूल्य तुलना (04-01-2021 तक)

नाम और विवरण (विशेष विवरण, मॉडल, सुविधाएँ)	GEM पर मूल्य (रुपए में)	Amazon, आधिकारिक वेबसाइट आदि पर मूल्य (रुपए में)	प्रस्ताव मूल्य में भिन्नता
Parker Jotter Standard Ball Pen	MRP: 250; Offer Price (OP): 210	Amazon.in- MRP: 250; OP: 188	+ 10.5%
Rorito Greetz Gel Pen Maxtron Gold Robotic Fluid Ink System Pen -Blue	MRP: 99; OP:87.95	Amazon- MRP: 99; OP: 64	+ 27.2%
Haier 1.5 Ton / 4500 kcal/hr High wall Split AC 5 Star Model:HSU19C-TFW5B(INV)	MRP: 65,000; OP: 58,500 Warranty: 2 year (Product), 10 year (compressor)	Amazon.in-MRP: 55,000; OP: 36,990 Warranty- 1 year (product); 12 years (compressor) Haier Website-Price: 42,990	+ 36.8%
Samsung 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV, Model: QA43Q60TAKXXL Resolution: 3840x2160	MRP: 78,900, OP: 70,998 Warranty- 1 Year	Amazon.in- MRP: 78,900, OP: 62,990 Warranty: 1 year comprehensive and 1-year additional warranty on Panel by Samsung	+ 11.3%
Omron White HEM 7156 Blood Pressure Monitor	MRP: 3,860, OP: 3,100 Warranty – 2 years	1mg.com- MRP: 3,860, OP: 2,860, Warranty – 3 years	+ 7.7%
HP LaserJet ENTERPRISE M607N Black and White Print Speed: >= 51 ppm	MRP: 1,22,921 OP: 1,10,625 Warranty – 3 Years	HP Website- MRP: 1,03,661 OP: 98,440 Warranty- 1 Year	+ 11.01%
Kores Easy Cut 871 Paper Shredder	MRP: 25,490, OP: 22,900	Amazon.in- MRP: 23,990 OP: 19,589	+ 14.5%

नाम और विवरण (विशेष विवरण, मॉडल, सुविधाएँ)	GEM पर मूल्य (रूपए में)	Amazon, आधिकारिक वेबसाइट आदि पर मूल्य (रूपए में)	प्रस्ताव मूल्य में भिन्नता
Hero Stainless Steel Bicycle for Men Model Name: Hero Lectro C3i 26 SS	MRP: 47,999 OP: 42,997	Hero Lectro (Choose my bicycle.com) OP: 32,499 Croma: MRP: 32,999, OP:32,990	(Gem vs Croma) + 23.3%
Milton 1500ml thermos	MRP: 1,560, OP: 1,100	Amazon: MRP: 1,454 OP: 1,199	- 9%
Nilkamal Dustbin 60 Litres	MRP: 3,100, OP: 1,175	Amazon- MRP: 1,990 OP: 1,448	- 23.2%
Nilkamal Veneto High Back Office Chair	MRP: 17,500, OP: 14,000	Nilkamal Website- MRP: 13,500, OP: 11,297.00	+ 19.3%
Bajaj Pulsar NS200 Motor Cycle	MRP: 1,15,250 OP: 1,15,250	Bajaj Auto website- MRP: 1,31,219 (Ex-showroom price in New Delhi)	- 13.9%
Godrej Interio Elite Mid Back Chair	MRP: 12,390, OP: 11,150	Godrej Interio website- MRP: 12,390	- 11.1%
Godrej Interio Steel Almirah 2400 mm (Slide N Store Compact Plus Wardrobe)	MRP: 31,022, OP: 27,919	Godrej Interio website- MRP: 32,572	- 16.7%
Godrej Interio Orlando 2-Seater Sofa	MRP: 51,800, OP: 46,620 Warranty- 1 year	Godrej Interio Website- MRP: 51,799, Warranty- 3 years	- 9.99%
Godrej Interio blue Zephyr Leisure Chair	MRP: 21,024, OP: 18,921	Godrej Interio Website- MRP: 21,022	- 11.1%
Honda Activa 6G DLX BS-VI Vehicle Engine Capacity (cc) 109.51	MRP: 60,767 OP: 60,767	Bikewale.com MRP:68,930 (Ex Showroom price)	- 13.4%
Apple MacBook Pro 16 inches 1TB MVVM2HN/A, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 4 GB Graphics Card	MRP: 2,73,800 OP: 2,45,679	Vijay Sales- MRP: 2,39,900, OP: 2,34,900 Tata Cliq- MRP: 2,39,900, OP: 2,27,900	(GEM vs Tata Cliq) + 7.2%

नाम और विवरण (विशेष विवरण, मॉडल, सुविधाएँ)	GEM पर मूल्य (रुपए में)	Amazon, आधिकारिक वेबसाइट आदि पर मूल्य (रुपए में)	प्रस्ताव मूल्य में भिन्नता
Dell Intel Core Desktop PC Monitor - E2720H Processor- i9 10900, RAM- 32 GB (DDR4) Expandable upto 128GB, HDD- 1000 GB HDD, SSD- 1024 GB, OS- Windows 10 Professional Graphics Card- 8 GB; NVIDIA GeForce RTX2070	MRP: 2,23,001 OP: 1,97,998 Warranty – 3 years	Dell Website (Desktop assembled with same specs)- 2,06,873 (Warranty: 3 year)	- 4.5%

स्रोत: GeM वेबसाइट, Amazon, Flipkart, विभिन्न कंपनियों की वेबसाइट

नोट: 4 जनवरी, 2020 को मूल्य, ओपी: प्रस्ताव मूल्य, एमआरपी: अधिकतम खुदरा मूल्य

तुलनात्मक कीमतों पर GeM की कीमतों में अंतर के रूप में भिन्नता की गणना की जाती है

(ग) लचीला कार्योंत्तर समाधान तंत्र बनाएँ

6.31 जब परिणाम अनिश्चित होते हैं, तो रेजिलिएंट एक्स-पोस्ट रिजॉल्यूशन तंत्र का होना महत्वपूर्ण है। प्रभावी पर्यवेक्षण पूर्व से निपटने के लिए सभी नियमों को लागू करने और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, एक मजबूत एक्स-पोस्ट रिजॉल्यूशन तंत्र को तैयार करना आवश्यक है। ग्रॉसमैन और हार्ट (1986) “अधूरे अनुबंध” पर काम करते हैं, यह दर्शाता है कि अनुबंध भविष्य की स्थिति पर आकस्मिक हैं और हर भावी राज्य के लिए पूर्ण अनुबंध, और विस्तार नियमों द्वारा लिखना संभव नहीं है। इस प्रकार, अनुबंधों और विनियमों, या जोखिम विश्लेषण में घटनाओं से पहले जटिलता जोड़ना इस मुद्दे को हल नहीं कर सकता है।

6.32 इसलिए, कुशल कानूनी प्रणालियों (यानी, अदालतों और संस्थानों) जैसे इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आदि की आवश्यकता है, हालांकि, कोर्ट सिस्टम एक्स-पोस्ट संकल्प के लिए एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण तरीका बना हुआ है। भारत में विवाद समाधान और अनुबंध प्रवर्तन के क्षेत्र में प्रदर्शन एक चिंता का विषय है और इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बैजनेस रिपोर्ट के अनुसार, OECD के उच्च आय वाले देशों में 589.6 दिनों और सिंगापुर में 120 दिनों की तुलना में भारत में वाणिज्यिक अनुबंध को हल करने में 1445 दिन लगते हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में मुकदमेबाजी की लागत का दावा मूल्य का लगभग 31 प्रतिशत है। यह ओईसीडी देशों (21 प्रतिशत) और भूटान (0.1 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है। भारत का प्रदर्शन अनुबंधों के प्रवर्तन का है, 2020 के लिए विश्व नियम कानून सूचकांक में इसकी रैंकिंग में भी देखा जाता है, जहाँ भारत 128 देशों में से 69 रैंक पर है। हमारा प्रदर्शन श्रेणी में सबसे खराब है ‘सिविल जस्टिस अनुचित विलंब के अधीन नहीं’ जहाँ हम 123 वें स्थान पर Venezuela, Guatemala, Peru, Bangladesh और Columbia (तालिका 7) से पीछे हैं।

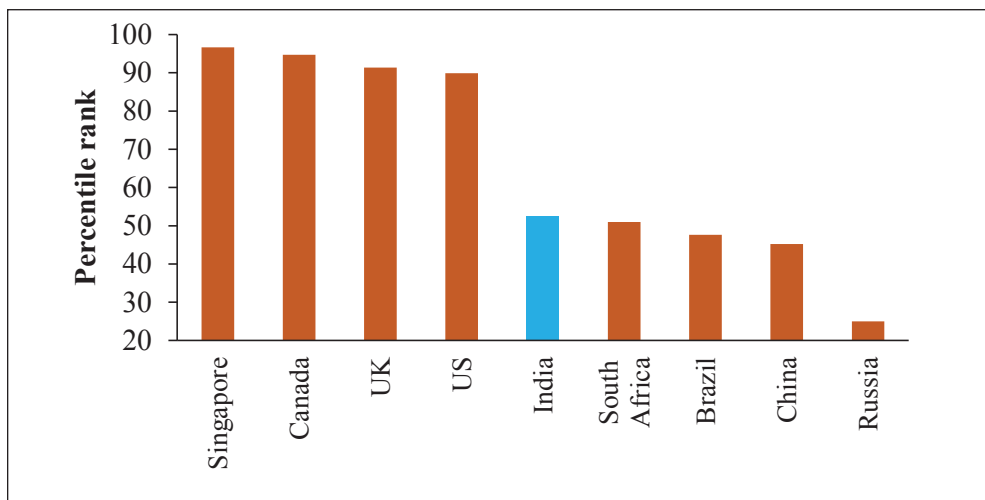
तालिका 7: विश्व नियम कानून (2020) क्रम-सूची में भारत की रैंक

विवरण	128 में से भारत रैंक
विश्व विधि नियम सूचकांक	69
लोग सिविल जस्टिस तक पहुंच सकते हैं और खर्च कर सकते हैं	115
सिविल जस्टिस अनुचित देरी के अधीन नहीं है	123
सिविल जस्टिस को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है	102
वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र सुलभ है	88

स्रोत: विश्व न्याय परियोजना (2020)

6.33 विश्व शासन सूचकांक के “नियम कानून” संकेतक उसी कहानी को दोहराते हैं। यूके और यूएस में 1.6 और 1.5 की तुलना में भारत क्रमशः ‘0’ से पीछे है और क्रमशः (चित्र 8)। भारत में विवाद समाधान और अनुबंध प्रवर्तन के लिए एक कुशल पूर्व-पोस्ट तंत्र होने के लिए कानूनी ढांचे में सुधार की आवश्यकता की ओर सभी ओर इशारा करते हैं।

चित्र 7: नियम संकेतक के क्रॉस कंट्री तुलना



स्रोत: विश्व बैंक

6.34 कानूनी प्रणाली के लिए आवश्यक है कि सिस्टम में घटना से पहले मुद्दों को ठीक न किया जाए, लेकिन पूर्व-पद विवाद समाधान तंत्र के रूप में उपयोग किया जाए। यह सरकार के निर्णय निर्माताओं के लिए उतना ही सही है जो बाद में पूछे गए उनके निर्णयों को पा सकते हैं। एक प्रभावी प्रवर्तन प्रणाली एकमुश्त धोखाधड़ी से अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होने वाले नकारात्मक परिणामों को अलग करने में सक्षम होनी चाहिए। देश में कानूनी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है जैसा कि अतीत में विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणों द्वारा तर्क दिया गया था।

प्रशासनिक प्रक्रिया सुधारों की दिशा

6.35 उपरोक्त दृष्टिकोण के कई निहितार्थ हैं जो पहले से ही हाल के सुधारों को सूचित कर रहे हैं। यहाँ दो हालिया उदाहरण हैं:

- श्रम संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए संसद और राज्य विधानसभा दोनों श्रम को विनियमित करने वाले कानूनों को बना सकते हैं। 100 से अधिक राज्य और 40 केंद्रीय कानून थे जो श्रम के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करते थे जैसे कि औद्योगिक विवादों के समाधान, काम करने की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा और मजदूरी, श्रम विनियमन के परिदृश्य को बहुत जटिल बनाते हैं। इसे सुधरने के लिए, सरकार ने मौजूदा 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम कोड में मिला दिया। मजदूरी पर कोड जुलाई 2019 में पारित किया गया था। सितंबर 2020 में, तीन बिल (i) औद्योगिक संबंध कोड, 2020, (ii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों पर कोड बिल, 2020 (iii) सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 पारित किए गए थे। संसद में।
- अन्य सेवा प्रदाताओं (OSP) के लिए नियामक ढांचा हाल ही में, पुराना और जटिल था। उदाहरण के लिए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) उद्योग तेजी से वैश्विक क्लाउड-आधारित सिस्टम पर चलता है, लेकिन भारतीय विनियमों ने इसके उपयोग को रोक दिया और स्थानीय EPABX पर जोर दिया। इसके अलावा, वर्क फ्रॉम होम और दुर्वह पंजीकरण आवश्यकताओं पर प्रतिबंध था। इसलिए, बीपीओ उद्योग के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, सरकार ने 5 नवंबर 2020 को OSP पर नए दिशानिर्देशों की घोषणा की। नए नियमों के तहत, OSP के लिए पंजीकरण की आवश्यकता पूरी तरह से दूर हो गई है और BPO उद्योग डेटा से संबंधित काम में लगा है। OSP नियमों के दायरे से बाहर ले जाया गया। इसी तरह, कई अन्य आवश्यकताएं, जिन्होंने कंपनियों को 'वर्क फ्रॉम होम' और 'वर्क फ्रॉम एनीवेयर' नीतियों को अपनाने से रोक दिया है। इसने BPO क्षेत्र के लिए नियमन को काफी उदार बनाया है। (खंड 2 के अध्याय संख्या 9 में विवरण देखें)

6.36 प्रक्रिया सादगी की आवश्यकता संस्थागत वास्तुकला तक भी फैली हुई है। पर्यवेक्षण का अंतिम स्रोत सार्वजनिक जांच और सार्वजनिक नेतृत्व है। चूंकि जनता के लिए सब कुछ जांचना संभव नहीं है, ध्यान कमजोर और सभी विकृत स्थिति के बजाय एक मजबूत लेकिन सीमित स्थिति पर होना चाहिए। यह सरकार के 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के विचार के अनुरूप है। आजादी के बाद से, स्वायत्त निकायों के बहुतायत ने प्रसार किया था। न केवल लागत दृष्टिकोण से, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल पर्यवेक्षण बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार छाँटने की आवश्यकता है। इस भावना में, पिछले वर्ष में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, कपास सलाहकार बोर्ड और जूट सलाहकार बोर्ड सहित कई संगठनों को बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार, शासन ने अपनी चार फिल्म मीडिया इकाइयों, फिल्मस डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी, भारत को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी।

6.37 अंत में, किसी नागरिक द्वारा सामना किए गए नियमों और विनियमों के बारे में किसी भी जानकारी की विषमता को समाप्त करने के लिए ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट लागू करने का मामला है। यह शुरुआत में आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 खंड 2 के अध्याय 8 में प्रस्तावित किया गया था। सुधार उस समस्या के लिए हल करता है जो अक्सर नियम बदलता है और अक्सर वर्तमान आवश्यकताओं को जानने के लिए नागरिक को परिपत्रों और सूचनाओं के एक लंबे पेपर निशान का पालन करना पड़ता है। इस अधिनियम के तहत, सभी विभागों को अपनी वेबसाइट पर सभी नागरिक-सामना करने वाले नियमों को अनिवार्य रूप से रखने की आवश्यकता होगी। अधिकारी स्पष्ट रूप से वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किसी भी नियम को लागू करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा, सभी कानूनों, नियमों और विनियमों को हर समय एक अद्यतन, एकीकृत के रूप में प्रस्तुत करना होगा। इससे पारदर्शिता आएगी और नियमों की समझ सरल होगी।

अध्याय एक नजर में

- ऐसी दुनिया में पूर्ण विनियम होना संभव नहीं है, जिसमें अनिश्चितता है क्योंकि सभी संभावित परिणामों के लिए इसका हिसाब-किताब करना संभव नहीं है। हालाँकि, सबूत बताते हैं कि भारत अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। यह प्रक्रिया के साथ अपेक्षाकृत अच्छे अनुपालन के बावजूद नियमों के निष्प्रभावी होने का परिणाम है।
- इस अध्याय में तर्क दिया गया है कि अति नियमन की समस्या का मूल कारण एक दृष्टिकोण है जो हर संभव परिणाम के लिए प्रयास करता है। यह भारत में किसी कंपनी को स्वेच्छा से बंद करने के लिए आवश्यक समय और प्रक्रियाओं के एक अध्ययन द्वारा चित्रित किया गया है, तब भी जब कोई बकाया विवाद या मुकदमा नहीं है।
- आर्थिक सिद्धांत और साक्ष्य दोनों यह दर्शाते हैं कि अनिश्चित और जटिल दुनिया में ऐसे विनियम लिखना संभव नहीं हैं जिसके सभी संभावित परिणाम निकल सकें। यह निर्णय लेने में विवेकाधिकार को अपरिहार्य बनाता है। हालांकि और अधिक जटिल विनियमों द्वारा विवेकाधिकार को कम करने के प्रयास से और भी अधिक गैर-पारदर्शी विवेकाधिकार उत्पन्न होगा। इसका समाधान यह है कि विनियमों को सरल किया जाए तथा अधिक पर्यवेक्षण में निवेश किया जाए जो परिभाषा के अनुसार कुछ विवेकाधिकार की अनुमति प्रदान करने की इच्छा व्यक्त करता है।
- विवेक, हालांकि, पारदर्शिता, पूर्व-जवाबदेही और पूर्व-पोस्ट रिजॉल्यूशन तंत्र की प्रणालियों के साथ संतुलित होने की आवश्यकता है। सार्वजनिक खरीद के लिए GeM पोर्टल के साथ अनुभव बताता है कि कैसे पारदर्शिता न केवल खरीद की कीमतों को कम करती है, बल्कि एक स्वच्छ प्रक्रिया के साथ ईमानदार निर्णय निर्माता भी प्रदान करती है।
- उपरोक्त बौद्धिक फ्रेमवर्क पहले से ही BPO क्षेत्र पर श्रम नियमों को हटाने से लेकर श्रम संहिता तक के सुधारों की सूचना दे चुका है। स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण में भी यही दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता है।

REFERENCES

- Arrow, K., & Debreu, G. (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. *Econometrica*, 22(3), 265-290. doi:10.2307/1907353
- Ashkenas, R. (2018, January 09). Is Dodd-Frank Too Complex to Work? Retrieved December 13, 2020, from <https://hbr.org/2012/03/is-dodd-frank-too-complex-to-w.html>
- Black, J., Dr. (2001, June). Managing Discretion. In *Penalties: Policy, Principles and Practice in Government Regulation*.
- Bolton, Patrick, and Mathias Dewatripont. *Contract theory*. MIT press, 2005.
- Braithwaite, J., Makkai, T., & Braithwaite, V. A. (2007). Dimensions of ritualism. In *Regulating aged care: Ritualism and the new pyramid* (pp. 235-236). Cheltenham, U.K.: Edward Elgar.
- Goetz, Charles J., and Robert E. Scott. "Principles of relational contracts." *Virginia law review* (1981): 1089-1150.
- Gundimeda, H., Sukhdev, P., Sinha, R. K., & Sanyal, S. (2007). Natural resource accounting for Indian states — Illustrating the case of forest resources. *Ecological Economics*, 61(4), 635-649. doi:10.1016/j.ecolecon.2006.07.035
- Hayek, A. (1974). The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred

Nobel 1974.

HART O. and Holmstrom B. (1987), "The Theory of Contracts," in Bewley T.F. (ed.), *Advances in Economic Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 71-155.

India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce. (2020). Report Of *The High-Level Advisory Group* (pp. 3-50).

Kanbur, R., & Ronconi, L. (2016, March). Labour laws: Strict rules are correlated with weak enforcement.

Knight, F. H. (1921) Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Company

Laffont, Jean-Jacques. 2005. Regulation and Development. Cambridge: Cambridge University Press.

Lorenz, E. N. (1963). Deterministic Nonperiodic Flow. *Journal of the Atmospheric Science*, 20, 130-141. doi:doi.org/10.1177/0309133308091948

Muller, J. Z. (n.d.). The Tyranny of Metrics.

Nagarajan, V. (2013). Discourses on Discretion and the Regulatory Agency. In Discretion and Public Benefit in a Regulatory Agency: The Australian Authorisation Process (pp. 129-168). ANU Press.

Nocera, J. (2012, January 17). Keep It Simple. Retrieved December 13, 2020, from <https://www.nytimes.com/2012/01/17/opinion/bankings-got-a-new-critic.html>

Raj, Rajesh S.N., Sen Kunal and Kar Sabyasachi. 2018. "Unmaking Make in India: Weak Governance, Good Deals and their Economic Impact". EPW, volume 55, Issue No. 11, 14 Mar 2020.

Ronaldson, M. (2006). Fighting Australia's Over-regulation.

Sanyal, S. (2020). *Risk Vs Uncertainty: Supervision, Governance & Skin-in-the-Game* (Vol. Discussion Paper I/2020-DEA) (India, Ministry of Finance, Department of Economics Affairs). Delhi.

SIMON H. A. (1959), "Theories of Decision Making in Economics and Behavioral Science," *The American Economic Review*, vol. 49, pp. 253-83.